



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 166-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2018 (ASVINA 6, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 सितम्बर 2018

संख्या 2/3/2018-R-II.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का० आ० 86/ह० अ० 24/1973/धा० 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का० आ० 86/ह० अ० 24/1973/धा० 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर 2013 में, पैरा 4 में, उप पैरा (iii), के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(iii) जिन्होंने सम्पत्ति कर पहले ही जमा करवा दिया है, तो उन्हें अधिक राशि, यदि कोई हो, का प्रतिदेय 3 प्रतिशत वार्षिक या सम्बन्धित नगरपरिषद तथा नगरपालिका के बचत बैंक खातों पर प्रोदभुत ब्याज दर जो भी अधिक हो, पर वापिस किया जायेगा”।

आनंद एम० शरण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय, विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 28th September, 2018

No. 2/3/2018-R-II.— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 69 read with sub-section (1) of the section 84 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.86/H.A.24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.86/H.A.24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013, in Para 4, for sub-Para (iii), the following sub-para shall be substituted, namely:-

- “(iii) Those who have already deposited the excess amount of property tax, if any, shall be refunded @ 3% per annum or as per the rate of interest available on saving bank account of the concerned Municipal Council and Municipal Committee, whichever is higher”.

ANAND M. SHARAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.